ISSN 2581-9917

अग्निवीर, अग्निपथ और सियासत

आशा त्रिपाठी*

वर्तमान राजनीति अपने कठिनतम और शायद कुरूपतम दौर से गुज़र रही है। एक अधैर्य की स्थिति बनी है जिसमें केन्द्र द्वारा लागू हर फैसले का विरोध करना ही मुख्य मुद्दा बन चुका है। यहां चर्चा का विषय है केन्द्र सरकार द्वारा सेना में जवानों की भर्ती के लिए लागू 'अग्निपथ' योजना है जो 2022 में लागू की गई। जिसका घोर विरोध करते हुए कई राज्यों में तोड़-फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं हुईं। ऐसी घटनाएं बेहद दुखी और आहत करती है जब सार्वजनिक संपत्तियों को उपद्रवियों द्वारा नष्ट किया जाता है। पर केन्द्र ने इस अडिग फैसले को जून 2022 में इसे लागू कर सितंबर में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पूर्व देश में सैनिकों की भर्ती पर गौर करें तो यह आँकड़ा पचास हजार से एक लाख के भीतर रहता था। इस बीच कोविड के चलते दो वर्ष तक भर्तियां बन्द थी, तकरीबन पूरा विश्व ही थम सा गया था। निश्चित तौर पर बेरोजगारी बढ़ी होगी। विशेषकर भारतीय सैन्य सेवाओं में जाकर देशसेवा करने के इच्छुक युवा बेरोजगार रह गए थे।

आज भी भारतीय सेना को हमारा समाज सम्मान की दृष्टि से देखता है। केन्द्र द्वारा इन सभी परिस्थितियों पर गौर कर,सेना के उच्च अधिकारियों, रक्षा विशेषज्ञों और सुरक्षा सलाहकारों से विमर्श कर अग्निपथ योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अन्तर्गत युवाओं को छः माह की कड़ी ट्रेनिंग के पश्चात् चार वर्ष के अनुबंध पर सेना में नियुक्तियों का अवसर प्रदान किया जाता है। लेकिन अनेक राजनीतिक पार्टियों ने इसे भी सियासी मुद्दा बना डाला। अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया में जब महज 40 हजार रिक्त पदों के लिए लाखों की संख्या में आए आवेदनों ने यह साबित कर दिया कि आज के युवाओं में रोजगार के अतिरिक्त देशप्रेम का जज्बा भी है। एक वर्ष में दो बार आयोजित, जल, थल और वायु सेना में लगभग एक लाख से अधिक अग्निवीर शामिल हो चुके हैं, जिनमें लगभग 200 महिलाएं हैं। यह महज 2023 से 2024 के आंकड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चन्नीरा चेनप्पा के अनुसार 2024-2025 में 50000 रिक्तयां फिर से जारी की गई हैं जिससे यह आंकडा डेढ़ लाख तक जा सकता है। इन अग्निवीरों में 25 प्रतिशत युवाओं का सेना में ही नियमितीकरण हो जाएंगे, अर्थात् हर चार से एक। शेष युवाओं के लिए तमाम सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है।

---

* स्वतंत्र लेखिका

अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य ही युवा अग्निवीर तैयार करना है जिन्हें सेना से जुड़े प्रशिक्षण देकर एक अनुशासित जीवन शैली, आत्मविश्वास और देशप्रेम की भावना विकसित करनी है। छः माह कठिन प्रशिक्षण, चार वर्ष की सैन्य सेवा के बाद 12 से 15 लाख का एकमुश्त भुगतान पाने के पश्चात युवाओं के सामने भविष्य के सैकड़ों रास्ते खुले होते हैं। इन पैसों से वह उच्च शिक्षा प्राप्त करें, स्वयं का रोजगार करें अथवा अन्य विभागों में पुनः नौकरी करें। चार साल की सैन्य सेवा का अनुभव उन्हें मजबूत बनाएगा और सेवा निवृत्ति के पश्चात मिली राशि उनमें इतना आत्मविश्वास भर देगा वे सामर्थ्यानुसार अपना भविष्य निर्धारित कर सकें। एक अग्निवीर को सेना छोड़ने के पश्चात् तकरीबन बारह लाख रुपये और पांच लाख की सेवा निधि राशि मिलती है। नौकरी के दौरान उसे एक सैनिक को मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें रहना, खाना, वर्दी और इलाज फ्री हैं। ऐसे में कई युवा बीस बाईस लाख तक बचा लेंगे। यहां यह भी उल्लेख करना जरूरी है कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाये तो उसके परिवार को 48 लाख रुपए की बीमा कव्हर राशि, 44 लाख अनुग्रह राशि, सेवा निधि राशि और शेष दिनों के संपूर्ण वेतन की राशि दी जाती है। ये सब लगभग एक करोड़ रुपए होती है। इसी तरह विकलांग हो जाने पर विकलांगता के प्रतिशत अनुसार 44 लाख 25 लाख, 10 लाख और शेष अवधि का पूरा वेतन, सेवा निधि राशि सहित दिया जाएगा।

अग्निवीर भर्तियों को लेकर आम युवाओं मे कितना उत्साह है यह गत नवंबर माह में हमने अपने शहर रायगढ़ में देखा जब छत्तीसगढ़ में रायगढ़ को भर्ती केन्द्र चुना गया। लगभग सात हजार युवाओ के रहने, भोजन व्यवस्था, परिक्षा केन्द्र तक पहुंचाने और वापसी की व्यवस्था प्रशासन और जन सहयोग से की गई। यह सब जिस कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ उसकी तारीफ करते हुए सेना से आए अधिकारियों ने भी कहा कि ऐसी व्यवस्था रेजिमेंटल सेन्टरों में भी नहीं होती। छत्तीसगढ़ विशेषकर रायगढ़ में सेना या फौज को लेकर जागरूकता का अभाव है। लेकिन अब कितनी जागरूकता आ चुकी है इसका उक्त भर्ती के दौरान उदाहरण देखने को मिला। तात्पर्य यह है कि अग्निपथ योजना जमीन से जुड़े उन युवाओं के लिए सेना में भर्ती की योजना है जो अपने पलटन की जान और शान दोनों होते हैं। ऐसे में इस योजना का विरोध करना प्रकारांतर में सेना का विरोध करना है।

'ताजा खबरों के अनुसार केन्द्र ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार उन 75 प्रतिशत को भी सेना में ले सकती है। ऐसे में विरोध करनेवालों कि यह दलील कि इससे सेना कमजोर हो सकती है समझ से परे है। सेना कमजोर होगी या नहीं यह भविष्य के गर्भ में है लेकिन इस योजना के बन्द होने से देश जरूर कमजोर होगा।'

चित्र सौजन्य लेखिका